अलाउद्दीन मियां और अन्य, शरीफ मियां और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

अप्रैल 13, 1989

[न्यायमूर्ति, एस. नटराजन और न्यायमूर्ति, ए.एम. अहमदी]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 235 और धारा 354(3)--सजा--निर्णय--सजा देने वाली अदालत प्रश्न को गंभीरता से ले--यह देखने का प्रयास करें कि सजा से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियां रिकॉर्ड पर लाई जाएं--सजा की गंभीरता लगाया गया-मौत की सजा के मामलों में न्यायाधीश के लिए आधार 'विशेष कारण खंड' इंगित करना अनिवार्य है, जो सजा की पसंद को स्पष्ट करने की बाध्यता को दर्शाता है।

भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा 34, 141, 149--गैरकानूनी जमावड़ा--किसी सदस्य पर परोक्ष जिम्मेदारी का बंधन--कार्य को साबित करने के लिए अभियोजन, जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया था।

अभियुक्त संख्या 1 से 6, एक गैरकानूनी सभा का गठन कर रहे थे जिसका सामान्य उद्देश्य बहारन मियां को मारना था, घातक हथियारों से लैस होकर उनके घर आए। बहारन मियाँ, गड़बड़ी की आशंका से, खुद को-आर्म के अंदर भागे लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें फिर से बाहर आने से रोक दिया। उस समय बहारन मियां की दो नवजात बेटियां करीब सात साल की सहाना खातून और करीब सात माह की चांद तारा उनके घर के दालान में खेल रही थीं. बहारन म्लान को मारने के अपने उद्देश्य में असफल होने पर, आरोपी नंबर 1 ने सहाना खातून के सिर, पेट और बाएं अंगूठे पर फरसा से वार किया, जिससे गंभीर चोटें आईं, और आरोपी नंबर 2 ने शिशु चंद तारा के सिर पर एक फरसा वार किया। इन चोटों के परिणामस्वरूप, सहाना खातून की उसी दिन मृत्यु हो गई, जबकि चांद तारा की 28 दिनों के बाद मृत्यु हो गई।

आरोपी नंबर 1 और 2 पर आईपीसी की धारा 302, 452 और 148 के तहत आरोप लगाए गए, जबकि आरोपी नंबर 3 से 6 को आईपीसी की धारा 302/149 के तहत परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाने की मांग की गई। आरोपी नंबर 3 और 4 पर आईपीसी की धारा 447 और 148 के तहत आरोप लगाए गए। और आरोपी संख्या 5 और 6 पर आईपीसी की धारा 447 और 147 के तहत आरोप लगाए गए, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी संख्या 1 और 2 को तीनों मामलों में दोषी ठहराया और धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन दोनों को मौत की सजा सुनाई। आरोपी संख्या 3 और 4 को आईपीसी की धारा 302/149, 447 और 148 के तहत दोषी ठहराया गया और धारा 302/149 के तहत अपराध के लिए उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। आरोपी संख्या 5 और 6 को धारा 302/149, 447 और 147, आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था। धारा 302/149, आईपीसी के तहत अपराध के लिए, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 1 और 2 की अपील खारिज कर दी और संदर्भ स्वीकार करते हुए, दो नवजात लड़कियों की हत्या के लिए उन्हें दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। हालाँकि, धारा 302/149 के

तहत शेष चार आरोपियों की दोषसिद्धि को धारा **326/149** में बदल दिया गया और उनमें से प्रत्येक को दी गई आजीवन कारावास की सजा को सात साल के कठोर कारावास की सजा से बदल दिया गया। हालाँकि, अन्य मामलों में उनकी दोषसिद्धि और सजाएँ बरकरार रखी गईं:

इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि **(1)** अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे; **(2)** नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा सिद्ध पाए गए तथ्यों पर भी, अभियुक्त संख्या **1** से **6** को धारा **149,** आईपीसी की सहायता से हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि दोनों लड़कियों की हत्या गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य से बाहर थी। **; (3)** मामले के तथ्य आरोपी संख्या **1** और **2** के मामले में मौत की सज़ा की गारंटी नहीं देते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि सीआरपीसी की धारा **235(2)** की प्रक्रियात्मक आवश्यकता का अक्षरश: पालन नहीं किया गया था; और **(4)** धारा **302,** आईपीसी, और धारा **354(3),** सीआरपी सी, जहां तक वे मृत्युदंड लगाने की अनुमति देते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद **14, 19** और **21** का उल्लंघन थे।

अदालत ने आरोपी संख्या **1** और **2** के मामले में मौत की सजा को धारा **302,** आईपीसी के तहत आजीवन कारावास में परिवर्तित करके और धारा **326/149** आईपीसी के तहत आरोपी संख्या **3** से **6** की सजा को रद्द करते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। ,

अभिनिर्धारित किया गया**: (1)** इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अविश्वसनीय हैं और आरोपी व्यक्तियों की सजा की पुष्टि के लिए उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

(2) यदि अभियोजन पक्ष ने कुछ व्यक्तियों की जांच नहीं की जो घटना स्थल पर मौजूद थे, यह जानने पर कि उन्हें जीत लिया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन आरोपी व्यक्तियों के प्रति अनुचित था। इन व्यक्तियों की गैर-परीक्षा अन्य अभियोजन गवाहों के साक्ष्य के संभावित मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है।

(3) धारा **149.** आई पी सी, बनाता है। विशिष्ट अपराध**.** चूँकि यह धारा रचनात्मक दंडात्मक दायित्व लगाती है, इसलिए इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए।

(4) धारा **149** को अधिनियमित करने में विधायिका का इरादा किसी गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को उसके एक या अधिक सदस्यों द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए दंड का भागी बनाना नहीं है। धारा **149** को लागू करने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि गैरकानूनी जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभियोगात्मक कार्य किया गया था। भले ही सामान्य उद्देश्य से संबंधित कोई कार्य गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया हो, यह अन्य सदस्यों के ज्ञान में होना चाहिए क्योंकि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है। यदि सभा के सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किसी विशेष अपराध किए जाने की संभावना को जानते थे या जानते थे तो वे धारा **149** के तहत इसके लिए उत्तरदायी होंगे। आई**.**पी**.**सी**.**

(5) प्रत्येक मामले में यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था या ऐसा था जिसके सदस्यों को पता था कि अपराध होने की संभावना है। सामान्य उद्देश्य और किए गए अपराध के बीच एक संबंध होना चाहिए, और यदि यह पाया जाता है कि यह सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध था, तो सभा का प्रत्येक सदस्य इसके लिए उत्तरदायी होगा।

(6) मौजूदा मामले में, गैरकानूनी जमावड़े का सामान्य उद्देश्य, जैसा कि आरोप में बताया गया है, बहारन मियां को मारना था। जब आरोपी नंबर **1** और **2** को एहसास हुआ कि बहारन मियां उनकी पहुंच से बाहर है. वे। अपने मिशन को पूरा करने में विफलता से निराश होकर, उन्होंने निर्दोष लड़कियों पर अपने हथियार चलाए, जो गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य का हिस्सा नहीं था। अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन दो लड़कियों को मारना जरूरी नहीं था जो आरोपी नंबर **1** और **2** के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में बाधक नहीं थीं। इसलिए, धारा **149** की सहायता से आरोपी संख्या **1** और **2** द्वारा दो नाबालिग लड़कियों को पहुंचाई गई चोटों के लिए आरोपी संख्या **3** से **6** को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(7) धारा **302,** आई पी सी, मृत्यु और आजीवन कारावास के बीच चयन करने का न्यायालय पर भारी कर्तव्य डालती है। जब अदालत को दोषी की पुकार 'मैं जीना चाहता हूं' और अभियोजक की मांग 'वह मरने का हकदार है' के बीच चयन करने के लिए कहा जाता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अदालत को सजा के चुनाव में उच्च स्तर की चिंता और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। **.**

(8) हमारी न्याय वितरण प्रणाली में कई कठिन निर्णय पीठासीन अधिकारी पर छोड़ दिए जाते हैं, कभी-कभी इसके लिए तराजू या वजन उपलब्ध कराए बिना। हालाँकि, हत्या के मामलों में, चूंकि विकल्प मृत्युदंड और आजीवन कारावास के बीच है, विधायिका ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **354** की उपधारा **(3)** के रूप में एक दिशानिर्देश प्रदान किया है।

(9) जब कानून न्यायाधीश पर कारण बताने का कर्तव्य डालता है तो इसका तात्पर्य यह है कि सजा के बारे में अपनी पसंद को स्पष्ट करना उस पर कानूनी दायित्व है। ऐसा कहना अटपटा लग सकता है, लेकिन उपरोक्त प्रावधान में 'विशेष कारण खंड' के अस्तित्व का तात्पर्य यह है कि न्यायालय उपयुक्त मामलों में मौत की चरम सजा लगा सकता है, जो इस तर्क को नकारात्मक करता है कि किसी से मिलने का कोई वैध कारण कभी नहीं हो सकता है। अपराधी को मौत की सज़ा, चाहे अपराध कितना भी क्रूर, वीभत्स या चौंकाने वाला क्यों न हो।

(10) जहां गंभीरता की सजा दी जाती है, यह जरूरी है कि न्यायाधीश को उस आधार का संकेत देना चाहिए जिस पर वह उस परिमाण की सजा को उचित मानता है। जब तक विशेष कारण न हों, विशेष मामले के तथ्यों के लिए विशेष, जिन्हें कड़ी सजा को उचित ठहराने के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है, न्यायाधीश मौत की सजा नहीं देगा। यदि कोई न्यायाधीश पाता है कि वह दो वाक्यों में से उच्च वाक्य को चुनने के आधार को उचित सटीकता के साथ समझाने में असमर्थ है, तो उसकी पसंद निचले वाक्य पर विफल होनी चाहिए।

(11) वाक्य का चुनाव संहिता की धारा **235** की उपधारा **(2)** में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया जाना है। चूंकि प्रावधान का उद्देश्य अभियुक्त को सजा के सवाल पर असर डालने वाली सभी प्रासंगिक सामग्री को अदालत के समक्ष रखने का अवसर देना है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रावधान हितकर है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(12) अभियुक्त की सुनवाई की आवश्यकता का उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के नियम को पूरा करना है। जीवन या मृत्यु के मामले में, पीठासीन अधिकारी को अभियुक्त के वैधानिक अधिकार के लिए उच्च स्तर की चिंता दिखानी चाहिए और इसे सजा का चुनाव करने से पहले पार की जाने वाली औपचारिकता मात्र नहीं मानना चाहिए। यदि अभियुक्त को अदालत के समक्ष अपने पूर्ववृत्त, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, कम करने वाली

और कम करने वाली परिस्थितियों आदि को रखने का प्रभावी और वास्तविक अवसर दिए बिना चुनाव किया जाता है, तो सजा पर अदालत का निर्णय कमजोर होगा।

(13) संहिता की धारा **235** की उप-धारा **(2)** की आवश्यकताओं का अक्षरश: पालन किए बिना लिए गए सजा संबंधी निर्णय को एक उचित आदेश द्वारा प्रतिस्थापित करना पड़ सकता है। मौजूदा मामले में, ट्रायल कोर्ट ने वास्तव में इसे महज एक औपचारिकता के रूप में माना, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने **31** मार्च, **1987** को अपराध का निष्कर्ष दर्ज किया था, और उसी दिन इससे पहले कि आरोपी सजा के सदमे को झेल सके और उबर सके। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें सज़ा के सवाल पर कुछ कहना है। इसके तुरंत बाद दोनों आरोपियों को मौत की सजा देने का फैसला सुनाया गया।

(14) एक सामान्य नियम के रूप में, ट्रायल कोर्ट को सजा दर्ज करने के बाद मामले को भविष्य की तारीख के लिए स्थगित कर देना चाहिए और अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष को भी सजा के सवाल पर प्रासंगिक सामग्री रखने के लिए कहना चाहिए और उसके बाद फैसला सुनाना चाहिए। अपराधी को दी जाने वाली सज़ा.

(15) मौजूदा मामले में, ट्रायल कोर्ट ने संहिता की धारा **235** की उपधारा **(2)** की अनिवार्य आवश्यकता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। उच्च न्यायालय ने भी जब मृत्युदंड की पुष्टि की तो सत्र न्यायाधीश के समक्ष केवल अल्प सामग्री ही रखी गई थी। अभियुक्तों के पूर्वजों, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, समुदाय पर उनके अपराध का प्रभाव आदि का विवरण न होने से सजा का चुनाव मुश्किल हो जाता है।

(16) यह आवश्यक है कि कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम सजा 'दुर्लभतम' मामलों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए जो असाधारण प्रकृति के हैं। अपराध की गंभीरता को दर्शाने, कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने, अपराध के लिए उचित सजा प्रदान करने, आपराधिक आचरण पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाने और समुदाय को आगे इसी तरह के आचरण से बचाने के लिए गंभीरता की सजाएं दी जाती हैं।

(17) वर्तमान मामले में, दुर्भाग्य से वाक्य के चयन के लिए सामग्री कम है। जैसा कि कहा गया है, अपराध का मकसद अस्पष्ट है। अर्थात् दोनों पक्षों के दो शिशुओं के बीच झगड़ा सही प्रतीत नहीं होता है। हत्याएं लाभ के लिए नहीं थीं। परिवर्तन से पता चलता है कि लक्ष्य बहारन मियां, पिता थे, न कि दो शिशु। दोनों शिशुओं की हत्या किसी भी आरोपी के ध्यान में नहीं थी. दोनों लड़कियाँ अपने लक्ष्य के भागने की हताशा के कारण अपराधियों के गुस्से का शिकार थीं। अपराध में ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं है जो मामले को असाधारण बना दे। केवल यह तथ्य कि शिशुओं को मार दिया जाता है, और अधिक के बिना, मामले को 'दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1980] 2 एससीसी 684; और मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1983] 3 एससीसी 470, का उल्लेख किया गया है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1988 की आपराधिक अपील संख्या 343 और 446।

सीआरएल ए संख्या 140 ऑफ़ 1987 और मृत्यु संदर्भ में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 8/4/1988 से। 1987 की संख्या 3 और सीआरएल। 1987 की संख्या 136.

अपीलकर्ताओं के लिए आर के गर्ग, सलमान खुर्शीद, राकेश लूथरा, इरशाद अहमद, विनायक डी फड़के, श्रीमती बिमला सिन्हा और गोपाल सिंह।

प्रतिवादी की ओर से ए शरण, डी गोबरधन, डी एन गोबरधन और बी बी सिंह।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायमूर्ति, अहमदी: विशेष अनुमति द्वारा इन दो अपीलों में अपीलकर्ता छह आरोपी व्यक्ति हैं जिन्हें मुकदमे के लिए विद्वान तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीवान के समक्ष पेश किया गया था। 1988 की आपराधिक अपील संख्या 343 मूल अभियुक्त संख्या 1, 2, 3 और 5 (अलाउद्दीन मियां, केयामुद्दीन मियां, साहेब हुसैन और अफजल मियां) द्वारा है और 1988 की आपराधिक अपील संख्या 466 मूल अभियुक्त संख्या 4 और 6 (सरीफ मियां और मैनुद्दीन) द्वारा है मियाँ)। सुविधा के लिए हम उन्हें ट्रायल कोर्ट में उनके मूल पदों से संदर्भित करेंगे।

आरोपी नंबर 1 और 2 पर आईपीसी की धारा 302, 452 और 148 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी नंबर 1 और 2 ने आरोपी नंबर 3 से 6 के साथ मिलकर एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था, जिसका सामान्य उद्देश्य था पीडब्लू 6 बहारन मियां को मारने के लिए और उक्त उद्देश्य के अनुसरण में आरोपी संख्या 1 ने लगभग सात वर्ष की सहाना खातून की मृत्यु का कारण बना और अभियुक्त संख्या 2 ने लगभग सात महीने की चांद तारा की मृत्यु का कारण बना। अभियुक्त संख्या 1 और 2 पर धारा 302, आईपीसी के तहत पर्याप्त आरोप लगाए गए, जबकि अभियुक्त संख्या 3 से 6 को धारा 302/149, आईपीसी के तहत परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाने की मांग की गई, अभियुक्त संख्या 3 और 4 पर धारा 447 और 148, आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए। और आरोपी संख्या 5 और 6 पर आईपीसी की धारा 447 और 147 के तहत आरोप लगाए गए, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी संख्या 1 और 2 को तीनों मामलों में दोषी ठहराया और धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन दोनों को मौत की सजा सुनाई। उनमें से प्रत्येक को आईपीसी की धारा 148 और 452 के तहत प्रत्येक मामले में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। मूल सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था। आरोपी संख्या 3 और 4 को आईपीसी की धारा 302/149, 447 और 148 के तहत दोषी ठहराया गया और धारा 302/149 के तहत अपराध के लिए उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। आईपीसी की धारा 148 और 447 के तहत अपराधों के लिए, उन्हें क्रमशः एक वर्ष और तीन महीने के कठोर कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया। मूल सजाएँ एक साथ चलाने का आदेश दिया गया। अभियुक्त संख्या 5 और 6 को धारा 302/149, 447 और 147, आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था। धारा 302/149, आईपीसी के तहत अपराध के लिए, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि धारा 447 और 147, आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें क्रमशः तीन महीने और छह महीने के लिए कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। मूल सजाएँ एक साथ चलाने का आदेश दिया गया। चूंकि अभियुक्त संख्या 1 और 2 को मृत्युदंड दिया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया गया था जिसे 1987 की संदर्भ संख्या 3 के रूप में क्रमांकित किया गया था। अभियुक्त संख्या 1, 2, 3 और 5 ने एक अपील को प्राथमिकता दी, 1987 की आपराधिक अपील संख्या 140 , ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए। अभियुक्त संख्या 4 और 6 ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ एक अलग अपील, 1987 की आपराधिक

अपील संख्या 136, को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भ एवं दोनों अपीलों का निस्तारण कर दिया गया। एक सामान्य निर्णय द्वारा न्यायालय. जहां तक आरोपी नंबर 1 और 2 का सवाल है, उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और संदर्भ स्वीकार करते हुए, दो नवजात लड़कियों की हत्या के लिए उन्हें दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। हालाँकि, धारा 302/149 के तहत शेष चार आरोपियों की दोषसिद्धि को धारा 326/149 में बदल दिया गया और उनमें से प्रत्येक को दी गई आजीवन कारावास की सजा को सात साल के कठोर कारावास की सजा से बदल दिया गया। हालाँकि, अन्य मामलों में उनकी दोषसिद्धि और सज़ा बरकरार रखी गई। विभिन्न मामलों में उन्हें दी गई दोषसिद्धि और सजाओं से व्यथित होकर सभी छह आरोपियों ने विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान दो अपीलें दायर की हैं।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष ने कहा कि 25 जुलाई 1985 की दोपहर लगभग 4.30 बजे जब पीडब्लू 6 बहारन मियां अपने घर के प्रवेश द्वार पर बैठे थे, उपरोक्त छह आरोपी व्यक्ति पश्चिम से घातक हथियारों से लैस होकर आए; आरोपी नंबर 1 और 2 'फरसा' लेकर थे, आरोपी नंबर 3 और 4 भाले (भाला) से लैस थे और आरोपी नंबर 5 और 6 लाठियों से लैस थे। उन्हें देखते ही पीडब्लू 6 उठकर अपने घर के 'ओसरा' (बरामदा) में चला गया। आरोपी संख्या 3 ने घर के सामने बंधी भैंस को खोलना शुरू कर दिया, जबकि अन्य आरोपियों ने पीडब्लू 6 को गालियां दीं, जिस पर उसने आपत्ति जताई। इस पर आरोपी नंबर 4 और 6 चिल्लाए 'सेल को जान से मार दो'। इसके तुरंत बाद, आरोपी नंबर 1 और 2 खतरनाक तरीके से पीडब्लू 6 की ओर बढ़े। दो शिशु सहाना खातून और चांद तारा तब पश्चिमी कमरे के बाहर 'दलान' में खेल रहे थे। आरोपी संख्या 1 और 2 को फारस से लैस होकर उसकी ओर आते देखकर पीडब्लू 6 को गड़बड़ी की आशंका हुई और वह खुद को भाले से लैस करने के लिए बगल के कमरे में भाग गया। हालाँकि, उसकी पत्नी, पीडब्लू 5 लैला खातून, जो कमरे में थी, ने उसे इस डर से बाहर जाने से रोक दिया कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसे मार डाला जा सकता है। यह महसूस करते हुए कि पीडब्लू 6 अंदर के कमरे में घुस गया है और उसकी पत्नी ने उसे बाहर आने से रोक दिया है, आरोपी नंबर 1 ने सहाना खातून के सिर, पेट और बाएं अंगूठे पर फरसा से वार किया, जिससे गंभीर चोटें आईं। अभियुक्त संख्या 2 ने शिशु चांद तारा के सिर पर एक फरसा से वार कर दिया. पड़ोसी पीडब्लू 2 फुल मोहम्मद मियां, पीडब्लू 3 अली असगर, पीडब्लू 4 विद्या गिरी और अन्य, अर्थात् जलालुद्दीन अहमद, सादिक मियां, राम चंद्र प्रसाद, भिखारी मियां, आदि ने हस्तक्षेप किया, हमलावरों को शांत किया और उन्हें दूर भेज दिया। हमलावरों के घटनास्थल से चले जाने के बाद दोनों घायल लड़कियों को सिटी डिस्पेंसरी में ले जाया गया जहां पीडब्लू 6 की पहली सूचना रिपोर्ट लगभग 6.45 पैरा मीटर पर दर्ज की गई। दुर्भाग्यवश, डिस्पेंसरी में भर्ती होने के कुछ ही समय बाद सहाना खातून की मृत्यु हो गई। उनकी छोटी बहन चांद तारा ने 23 अगस्त, 1985 को दम तोड़ दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए डिस्पेंसरी में ले जाने के तुरंत बाद, पीडब्लू 7 डॉ. हलीवंत सिंह, जिन्होंने सहाना खातून की जांच की, ने पाया कि उसके पिछले हिस्से में तेज चोट लगी थी। सिर के कारण कपाल की हड्डी टूट गई और मस्तिष्क का पदार्थ बाहर निकल आया, बाएं इलियाओ फोसा पर तेज काटने वाली चोट लगी और बाएं अंगूठे और बाईं तर्जनी पर तेज काटने वाली चोट लगी। सीवान सदर अस्पताल के वरिष्ठ सहायक सर्जन, पीडब्लू 1 डॉ. अनिल कुमार वर्मा ने 26 जुलाई, 1985 की दोपहर को सहाना खातून के शव का पोस्टमार्टम किया। चूँकि इस तथ्य पर विवाद नहीं है कि सहाना खातून की मृत्यु एक मानव हत्या थी। हमें पीडब्लू 1 द्वारा उसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि पीडब्लू 1 की राय में मृत्यु पीड़ित को फार्सा से लगी चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी।

घायल चंद तारा की उसी दिन पीडब्लू 7 द्वारा जांच की गई थी। उसने देखा था कि सिर के अगले आधे हिस्से पर मध्य रेखा के दाईं ओर एक तेज काटने वाली चोट थी और मस्तिष्क का पदार्थ पीछे के आधे हिस्से से बाहर आ रहा था। उन्हें एक इनडोर मरीज के रूप में भर्ती कराया गया था, लेकिन 13 अगस्त, 1985 को छुट्टी दे दी गई। कुछ दिनों बाद 23 अगस्त, 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। पीडब्लू 10 डॉ. अहमद ने चांद तारा के शव का शव परीक्षण किया और उन्होंने पाया कि वह संक्रमित थी। अल्सर 3" x 1-1/4" कपाल गुहा द्वारा सिर के पूर्वकाल भाग पर मस्तिष्क के साथ गहराई से संचारित होता है, विच्छेदन पर मेनिन्जिटीज और मस्तिष्क पदार्थ संकुलित पाए गए। उनके विचार में, फरसा जैसे तेज काटने वाले हथियार से लगी चोट से उत्पन्न संक्रमण के कारण होने वाला मेनिनजाइटिस और एन्सेफलाइटिस ही मृत्यु का कारण था। उपरोक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि चाँद तारा की मृत्यु भी मानवघाती मृत्यु हुई।

उपरोक्त तीन चिकित्सकों अर्थात् पीडब्लू 1, पीडब्लू 7, और पीडब्लू 10 के स्पष्ट साक्ष्यों के मद्देनजर यह निष्कर्ष कि दोनों लड़कियों की मृत्यु एक मानव वध के रूप में हुई, अप्राप्य है। सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं और यदि तो, किस हद तक? छह आरोपियों के खिलाफ दोष साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने घटना के पांच चश्मदीद गवाहों की जांच की, अर्थात् पीडब्लू 2 से 6। इन पांच चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन पक्ष का मामला उजागर किया है कि छह आरोपी व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था, जिसका सामान्य उद्देश्य था जिसमें पीडब्लू 6 बहारन मियां को मारना था। उस सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में, वे फरसा, भाला और लाठियों जैसे हथियारों से लैस होकर, 25 जुलाई, 1985 की शाम को पीडब्लू 6 के आवासीय परिसर में घुस गए और पहले निर्धारित कृत्यों को अंजाम दिया। निचली अदालतों ने पाया कि उस समय घर में पीडब्लू 5 और 6 की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता था। वास्तव में ये आरोपी व्यक्ति पीडब्लू 6 को मारने के लिए घर आए थे। पीडब्लू 2, 3 और 4 जिन्हें भरोसेमंद गवाह कहा जा सकता है, ने भी पीडब्लू 5 और 6 के अनुसार अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। इन अभियोजन गवाहों के साक्ष्य कायम हैं इसकी पुष्टि पीडब्लू 7 के साक्ष्यों से भी होती है, जिन्होंने घटना के तुरंत बाद दो घायलों के घावों को देखा था। पीडब्लू 1 और 10 जिन्होंने शवों का पोस्टमार्टम किया, वे भी चश्मदीद गवाहों की गवाही की पुष्टि करते हैं। इसलिए, निचली अदालतों ने पहले बताए गए उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, अभियुक्त के विद्वान वकील ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

1. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए पेश किए गए सबूत, विशेष रूप से पीडब्लू 2 से 6 के सबूत, विश्वसनीय नहीं हैं और उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

2. यहां तक कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा सिद्ध पाए गए तथ्यों पर भी, चार आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् आरोपी संख्या 3 से 6 को आईपीसी की धारा 149 की सहायता से हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि दोनों लड़कियों की हत्या सामान्य से बाहर थी। गैरकानूनी जमाव का उद्देश्य

3. भले ही दो लड़कियों की हत्या के लिए आरोपी नंबर 1 और 2 की सजा की पुष्टि हो गई हो, मामले के तथ्य मौत की सजा की गारंटी नहीं देते हैं, खासकर सीआरपीसी की धारा 235(2) की प्रक्रियात्मक आवश्यकता के कारण। अक्षरश: पालन नहीं किया गया, और

4. धारा 302, आईपीसी, और धारा 354(3), सीआरपीसी, जहां तक वे मृत्युदंड लगाने की अनुमति देते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन हैं।

हम इन विवादों से निपटने के लिए तुरंत आगे बढ़ेंगे।

विद्वान वकील श्री गर्ग ने हमें संतुष्ट करने के उद्देश्य से पांच चश्मदीद गवाहों के साक्ष्यों से हमें अवगत कराया कि घटना के संबंध में उनका बयान दोषमुक्त नहीं था और उनके साक्ष्यों पर पूरी तरह से भरोसा करना बेहद असुरक्षित होगा। हमने उपरोक्त पांच चश्मदीद गवाहों के साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की है और हमारा मानना है कि उनके साक्ष्यों की नीचे की दोनों अदालतों द्वारा सही ढंग से सराहना की गई थी। उस समय घर में दो पीड़ित लड़कियों के माता-पिता, पीडब्लू 5 और 6 की उपस्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, आरोपी व्यक्तियों ने दो लड़कियों के पिता, पीडब्लू 6 की हत्या करने के उद्देश्य से एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था। उस घोषित वस्तु के साथ, वे घातक हथियारों से लैस होकर, पीडब्लू 6 पर हमला करने के लिए गए। आरोपी संख्या 3 द्वारा पीडब्लू 6 के विरोध के बावजूद भैंस को खोलने के बाद, आरोपी संख्या 4 और 6 ने पीडब्लू 6 को मारने का आह्वान किया। इस कॉल से आरोपी नंबर 1 और 2 खतरनाक तरीके से पीडब्लू 6 की ओर बढ़े जो उस समय 'ओसरा' में खड़ा था। यह महसूस करते हुए कि आरोपी नंबर 1 और 2 उसे मारने के लिए निकले थे, पीडब्लू 6 अपने बचाव के लिए भाला लाने के लिए कमरे के अंदर गया। उसकी पत्नी पीडब्लू 5 जो कमरे में थी और उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था, वह उसके रास्ते में खड़ी हो गई और उसे बाहर जाकर आरोपी नंबर 1 और 2 का सामना करने की अनुमति नहीं दी। पीडब्लू 2, 3 और 4, जो पड़ोसी थे, ने घटना को करीब से देखा। आरोपी नंबर 1 और 2 ने दलान में खेल रही दो लड़कियों पर फरसा से जानलेवा हमला किया। पीडब्लू 2, जो पीडब्लू 6 का भाई है, घर के पूर्व में मैदान में था और इसलिए, घटना को देखने की स्थिति में था। पीडब्लू 3 बाज़ार से लौट रहा था जब उसने अभियुक्तों को पीडब्लू 6 के दरवाजे पर देखा। उसने अभियुक्तों को गालियाँ देते हुए और अभियुक्त संख्या 4 और 6 द्वारा पीडब्लू 6 को मारने के लिए दी गई कॉल को सुना। उसने अभियुक्तों को अंदर प्रवेश करते हुए भी देखा। घर और उस कमरे की ओर जा रहा था जिसमें पीडब्लू 6 एक भाला लाने के लिए दाखिल हुआ था। अंत में उसने आरोपी नंबर 1 और 2 को दोनों लड़कियों पर फार्सा से वार करते देखा। उनसे विस्तार से जिरह की गई, लेकिन यहां-वहां छोटे-मोटे विरोधाभासों को छोड़कर, जिनकी तभी उम्मीद/उम्मीद की जाती है जब कोई गवाह समय बीतने के बाद गवाही देता है, अभियोजन पक्ष के मामले को हिलाने वाली कोई भी ठोस बात उसे बदनाम करने के लिए सामने नहीं आई है। पीडब्लू 4 राम चंद्र प्रसाद की आरा मिल पर था जब उसने आरोपी व्यक्तियों को पश्चिम से आते और पूर्व की ओर बढ़ते देखा। उसने इन व्यक्तियों को पीडब्लू 6 के घर की ओर जाते देखा और उन्हें गालियाँ देते हुए सुना। उनकी जिरह में यह दिखाने का प्रयास किया गया किं वह उस समय राम चद्र प्रसाद की आरा मिल में उपस्थित नहीं हो सकते थे क्योंकि वह एक सरकारी कर्मचारी थे और माना जाता है कि उनकी सामान्य ड्यूटी का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक था। आगे यह दिखाने का प्रयास किया गया कि वह भिखारी दास और सीता राम प्रसाद के बीच कुछ जमीन के कब्जे के संबंध में सीआरपीसी की धारा 145 के तहत लंबित एक मामले से जुड़ा था। उन्होंने भूमि के एक अन्य टुकड़े के संबंध में भिखारी दास और मैनुद्दीन मियां के बीच किसी भी विवाद की जानकारी से भी इनकार किया है। यह साबित करने के लिए कि वह एक इच्छुक और पक्षपाती गवाह था, उससे लंबी जिरह की गई। भले ही इस गवाह के साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया जाए, नीचे दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं। इसलिए, हमारी राय है कि अभियुक्तों के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि की पुष्टि के लिए उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

अभियुक्तों के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाह, अर्थात् जल्लालुद्दीन, भिखारी मियां और राम चंद्र प्रसाद, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना स्थल पर मौजूद थे और उन्होंने पूरी घटना देखी थी, उन्हें जानबूझकर हटा दिया गया था। सच को दबाने का नजरिया. हम इस तर्क को इस साधारण कारण से स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि पीडब्लू 5 और पीडब्लू 6 दोनों के यह कहने के अलावा कि उन पर बचाव पक्ष द्वारा दबाव डाला गया था, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैराग्राफ 36 में पाया है कि बचाव पक्ष द्वारा गवाहों को डराने के प्रयास किए गए थे। सबूत देने से. यह निष्कर्ष निकालने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों पर गवाह बॉक्स से दूर रहने के लिए काफी दबाव डाला गया था। कुछ ने धमकियों और दबाव के आगे घुटने टेक दिए जबकि कुछ अन्य ने ऐसा नहीं किया और सबूत देने और सच बताने का साहस दिखाया। इस पृष्ठभूमि में, यदि अभियोजन पक्ष ने यह जानने के बाद कि जलालुद्दीन, राम चंद्र प्रसाद और भिखारी मियां से पूछताछ नहीं की, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन आरोपी व्यक्तियों के प्रति अनुचित था। श्री गर्ग ने कहा कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आरोपी व्यक्ति किसी भी तरह से गवाहों पर दबाव डालने या धमकी देने के दोषी थे। यह बात अलग है. प्रासंगिक बात यह है कि ऐसा ही हुआ। इसलिए, उपरोक्त गवाहों की गैर-परीक्षा अन्य अभियोजन गवाहों के साक्ष्य के संभावित मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है।

अब हम इस पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या अभियुक्त संख्या 1 और 2 के कृत्यों के लिए धारा 149 की सहायता से अभियुक्त संख्या 3 से 6 को उचित रूप से दोषी ठहराया गया है। धारा 141, आईपीसी, एक गैरकानूनी सभा को पांच या अधिक व्यक्तियों की एक सभा के रूप में परिभाषित करती है जिनकी आम सहमति होती है। इसका उद्देश्य उसमें उल्लिखित पांच कृत्यों में से किसी एक को करना है। उस धारा की व्याख्या यह स्पष्ट करती है कि एक सभा जो एकत्रित होने पर गैरकानूनी नहीं थी, बाद में एक गैरकानूनी सभा बन सकती है। धारा 142 में कहा गया है: जो कोई भी, उन तथ्यों से अवगत होते हुए, जो किसी सभा को गैरकानूनी सभा बनाते हैं, जानबूझकर उस सभा में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, उसे गैरकानूनी सभा का सदस्य कहा जाता है। धारा 143 गैरकानूनी सभा का सदस्य होने के लिए सज़ा निर्धारित करती है। धारा 144 में घातक हथियारों से लैस गैरकानूनी सभा में शामिल होने पर सजा का प्रावधान है। धारा 145 किसी गैरकानूनी जमावड़े में शामिल होने या बने रहने के लिए सज़ा निर्धारित करती है जिसे तितर-बितर करने का आदेश दिया गया है। धारा 146 दंगे को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि जब भी किसी गैरकानूनी सभा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगे के अपराध का दोषी होता है। धारा 147 फिर दंगे के लिए सज़ा निर्धारित करती है। धारा 148 घातक हथियारों से लैस गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा दंगा करने के लिए सजा निर्धारित करती है। इसके बाद धारा 149 आती है जो इस प्रकार है:

> "यदि किसी गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कोई अपराध किया जाता है, या जैसे कि उस सभा के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य के अभियोजन में अपराध किए जाने की संभावना है, तो प्रत्येक व्यक्ति, उस अपराध को करने के समय, उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है।"

इसलिए, किसी गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य पर पारस्परिक जिम्मेदारी तय करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपराध का गठन करने वाला कार्य उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया था या किया गया कार्य ऐसा है जैसा कि उस सभा के सदस्यों को पता था। उस सभा

के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन के लिए प्रतिबद्ध होने की संभावना है। इस धारा के तहत, इसलिए, एक गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य खुद को किसी अन्य सदस्य या उस सभा के सदस्यों के आपराधिक कृत्य या कृत्यों के लिए उत्तरदायी बनाता है, बशर्ते कि यह सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया हो या ऐसा हो/हो। उस सभा के सदस्य को पता था कि प्रतिबद्ध होने की संभावना है। यह धारा एक विशिष्ट अपराध बनाती है और गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को घटना के दौरान किए गए अपराध या अपराधों के लिए उत्तरदायी बनाती है, बशर्ते कि वे सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में प्रतिबद्ध थे/थे या उस के सदस्यों के समान थे/थे असेंबली प्रतिबद्ध होने की संभावना जानती थी। चूँकि यह धारा एक रचनात्मक दंडात्मक दायित्व लगाती है, इसलिए इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए क्योंकि यह गैरकानूनी सभा के सदस्यों को उनके सहयोगी या सहयोगियों द्वारा सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए अपराध या अपराध के लिए दंडित करना चाहता है। प्रत्येक मामले में यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था या ऐसा था जिसके सदस्यों को पता था कि अपराध होने की संभावना है। सामान्य उद्देश्य और किए गए अपराध के बीच एक संबंध होना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि यह सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध था, तो सभा का प्रत्येक सदस्य इसके लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए, धारा 141 में उल्लिखित पांच उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक के अभियोजन में किसी गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा किया गया कोई भी अपराध, गैरकानूनी सभा का गठन करने वाली उसकी कंपनियों को धारा 149, आईपीसी की सहायता से वर्तमान मामले में उस अपराध के लिए उत्तरदायी बना देगा। जैसा कि आरोप में बताया गया है, गैरकानूनी जमावड़े का सामान्य उद्देश्य पीडब्लू 6 बहारन मियां को मारना था। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आरोपी नंबर 1 और 2 पीडब्लू 6 के पीछे चले गए। खतरे को भांपते हुए पीडब्लू 6 खुद को बचाने के लिए भाला लाने के लिए बगल के कमरे में भाग गया। हालाँकि, उसकी पत्नी पीडब्लू 5 ने उसका रास्ता रोक दिया और उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। जब आरोपी नंबर 1 और 2 को एहसास हुआ कि पीडब्लू 6 उनकी पहुंच से बाहर है, तो उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने में विफलता से निराश होकर, दालान में खेल रही मासूम लड़कियों पर अपने हथियार लहराए। इस प्रकार सामान्य उद्देश्य से निराश होकर, आरोपी संख्या 1 और 2 ने निर्दोष लड़कियों पर अपना क्रोध निकाला, जो कि गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य का हिस्सा नहीं था। पीडब्लू 6 को मारने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन लड़कियों को मारना जरूरी नहीं था क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने उन्हें पीडब्लू 6 तक पहुंचने से नहीं रोका था। इसलिए, आरोपियों के वकील ने सही ही कहा कि आरोपी संख्या 1 और 2 को दंडित किया जा सकता है। सामान्य वस्तु के विफल हो जाने और खुद को उनकी पहुंच से परे रखकर पीडब्लू 6 पर छोड़ दिए जाने के बाद किए गए उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए, गैरकानूनी सभा के अन्य सदस्यों को आरोपी संख्या 1 और 2 के कृत्यों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था क्योंकि लड़कियों की हत्या नहीं थी असेंबली की सामान्य वस्तु का हिस्सा। एक बार जब पीडब्लू 6 उसके दो उत्पीड़कों की पहुंच से बाहर हो गया, तो उसे मारने का सामान्य उद्देश्य विफल हो गया और उसके बाद व्यक्तिगत सदस्यों ने जो कुछ भी किया, वह सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में नहीं किया गया कहा जा सकता था। धारा 149 को लागू करने में विधायिका का इरादा किसी गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को उसके एक या अधिक सदस्यों द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए दंड का भागी बनाना नहीं है। धारा 149 को लागू करने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि गैरकानूनी जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभियोगात्मक कार्य किया गया था। भले ही सामान्य उद्देश्य से संबंधित कोई कार्य गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया हो, यह अन्य सदस्यों की जानकारी में होना चाहिए क्योंकि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन के लिए ऐसा कृत्य किए जाने की संभावना है। यदि सभा के सदस्यों को सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किसी विशेष अपराध किए जाने की

संभावना के बारे में पता था या वे जागरूक थे, तो वे आईपीसी की धारा 149 के तहत इसके लिए उत्तरदायी होंगे, हालांकि, तत्काल मामले में, गैरकानूनी सभा का गठन करने वाले सदस्य पीडब्लू 6 को मारने के लिए उसके घर गया था। वह गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य था। उस सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन दो लड़कियों को मारना जरूरी नहीं था जो आरोपी नंबर 1 और 2 के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में बाधा नहीं थीं। इसलिए, हमारी राय है कि धारा 149, आईपीसी की सहायता से आरोपी संख्या 1 और 2 द्वारा दो नाबालिग लड़कियों को पहुंचाई गई चोटों के लिए आरोपी संख्या 3 से 6 को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए हम धारा के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर देते हैं। 326/149, आई पी सी, और उस मामले में आरोपी संख्या 3 से 6 को भी सजा सुनाई गई। हालाँकि, हम आरोपी नंबर 3 और 4 को आईपीसी की धारा 447 और 148 के तहत दोषी मानते हैं, और उन मामलों में उन्हें दी गई सजा की पुष्टि करते हैं। इसलिए हम आरोपी संख्या 5 और 6 को आईपीसी की धारा 447 और 147 के तहत दोषी मानते हैं और उक्त अपराध के लिए उनकी सजा की पुष्टि करते हैं।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि अलाउद्दीन मियां और केयंबुद्दीन मियां हत्या के दोषी हैं, अगला सवाल यह है कि उन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए, अर्थात् जीवन का अंत या आजीवन कारावास। आईपीसी की धारा 302 अदालत पर मौत और आजीवन कारावास के बीच चयन करने का भारी कर्तव्य डालती है। जब अदालत को दोषी के रोने 'मैं जीना चाहता हूं' और अभियोजक की मांग 'वह मरने का हकदार है' के बीच चयन करने के लिए कहा जाता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अदालत को सजा के चुनाव में उच्च स्तर की चिंता और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। हमारी न्याय वितरण प्रणाली में कई कठिन निर्णय पीठासीन अधिकारियों पर छोड़ दिए जाते हैं, कभी-कभी इसके लिए तराजू या वजन उपलब्ध कराए बिना। हालाँकि, हत्या के मामलों में, चूंकि विकल्प मृत्युदंड और आजीवन कारावास के बीच है, इसलिए विधायिका ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 ("संहिता") की धारा 354 की उपधारा (3) के रूप में एक दिशानिर्देश प्रदान किया है, जिसमें लिखा है निम्नानुसार:

> "जब किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि मौत से दंडनीय है या, वैकल्पिक रूप से, आजीवन कारावास या वर्षों की कारावास से दंडनीय है, तो निर्णय में दी गई सजा के कारणों को बताया जाएगा, और, मौत की सजा के मामले में, ऐसी सजा के विशेष कारण।"

यह प्रावधान मृत्युदंड या आजीवन कारावास या वर्षों की अवधि के लिए दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि के मामलों में दोषी को दी गई सजा के समर्थन में कारण बताने को अनिवार्य बनाता है और आगे यह आदेश देता है कि यदि न्यायाधीश मृत्युदंड देता है। दंड, ऐसी सजा के लिए "विशेष कारण" निर्णय में बताए जाएंगे। जब कानून न्यायाधीश पर कारण बताने का कर्तव्य डालता है तो इसका तात्पर्य यह है कि सजा के बारे में अपनी पसंद को स्पष्ट करना उस पर कानूनी दायित्व है। ऐसा कहना अटपटा लग सकता है, लेकिन उपरोक्त प्रावधान में 'विशेष कारण खंड' के अस्तित्व का तात्पर्य है कि न्यायालय उपयुक्त मामलों में मौत की चरम सजा दे सकता है जो इस तर्क को नकारात्मक करता है कि यात्रा करने का कोई वैध कारण कभी नहीं हो सकता है मृत्युदंड वाला अपराधी, चाहे अपराध कितना भी क्रूर, वीभत्स या चौंकाने वाला क्यों न हो। मानवतावादी विचारधारा या पुनर्वासवादी दर्शन के रूप में वर्णित अपने तर्क को आधार बनाते हुए, श्री गर्ग ने प्रस्तुत किया कि कोई भी कानून जो जीवन के सर्वोच्च अधिकार को एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में राज्य की विफलता के लिए बलिदान करने की अनुमति देता है जिसमें ऐसे अपराध नहीं किए जाते हैं, अवश्य किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करने वाला मानते हुए इसे रद्द कर दिया जाए। मृत्युदंड को

समाप्त करने के लिए सुधारवादी सिद्धांत के नायक की मांग को खारिज करते हुए विधायिका ने अपने विवेक से सोचा कि 'विशेष कारण खंड' अत्यधिक दंड के मनमाने ढंग से लगाए जाने के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय होना चाहिए। जहां गंभीरता की सजा दी जाती है, वहां यह जरूरी है कि न्यायाधीश को वह आधार बताना चाहिए जिसके आधार पर वह उस परिमाण की सजा को उचित मानता है। जब तक विशेष कारण न हों, विशेष मामले के तथ्यों के लिए विशेष, जिन्हें कड़ी सजा को उचित ठहराने के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है, न्यायाधीश मौत की सजा नहीं देगा। यह कहा जा सकता है कि यदि एक न्यायाधीश को लगता है कि वह दो वाक्यों में से उच्च वाक्य को चुनने के आधार को उचित सटीकता के साथ समझाने में असमर्थ है तो उसकी पसंद निचले वाक्य पर होनी चाहिए। ऐसे सभी मामलों में कानून न्यायाधीश पर प्रत्येक मामले के पक्ष और विपक्ष की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद अपनी पसंद बनाने का दायित्व डालता है। यह तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए कि समुदाय में कंपकंपी पैदा करने वाले कुछ विशेष रूप से क्रूर अपराधों के अपराधियों से समुदाय को ऐसे अपराधों के अपराधियों से बचाने के लिए सख्ती से निपटना होगा। जहां एक निश्चित अपराध की घटना तेजी से बढ़ रही है और खतरनाक रूप धारण कर रही है, उदाहरण के लिए, एसिड डालना या पुल जलाना, अदालतों के लिए समुदाय की रक्षा करने और दूसरों को ऐसे अपराध करने से रोकने के लिए अनुकरणीय दंड देना आवश्यक हो सकता है। चूंकि विधायिका ने अपने विवेक से सोचा कि कुछ दुर्लभ मामलों में दूसरों को डराने और समाज और किसी मामले में देश की रक्षा के लिए मौत की चरम सजा देना अभी भी आवश्यक हो सकता है, इसलिए उसने सजा का विकल्प न्यायपालिका पर छोड़ दिया। शर्त यह है कि न्यायाधीश दोषी को कड़ी सजा दे सकता है, बशर्ते ऐसा करने के लिए विशेष कारण मौजूद हों। इस वैधानिक प्रावधान के सामने, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा नहीं लिया जाएगा, हम वकील के मौत के प्रति अत्यधिक समर्पण का सामना करने में असमर्थ हैं। किसी भी मामले में नहीं। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1980] 2 एससीसी 684 मामले में इस न्यायालय ने यह दलील खारिज कर दी थी कि मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। हालांकि, श्री गर्ग ने कहा कि उक्त निर्णय पर पुनर्विचार की जरूरत है। चूँकि बहुमत का गठन करने वाले विद्वान न्यायाधीशों को भगवती, जे के विचारों का लाभ नहीं मिला, जिन्होंने इसके विपरीत फैसला सुनाया। हम इस दलील से प्रभावित नहीं हैं, इसका सीधा सा कारण यह है कि जो कारण भगवती जे के साथ प्रबल थे, वे बहुमत का गठन करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के लिए अज्ञात नहीं हो सकते थे।

दंड संहिता के प्रावधानों पर एक साधारण नज़र डालने से भी पता चलेगा कि दंडों को अपराधों की गंभीरता के अनुरूप सावधानीपूर्वक वर्गीकृत किया गया है; गंभीर गलतियों के लिए निर्धारित दंड सख्त हैं जबकि छोटे अपराधों के लिए उदारता दिखाई जाती है। यहां फिर से पैंतरेबाज़ी के लिए काफी जगह है क्योंकि सज़ा का विकल्प केवल बाहरी सीमाओं के साथ न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ऐसे कुछ ही मामले हैं जिनमें न्यूनतम सज़ा का प्रावधान है। तो फिर सवाल यह है कि न्यायाधीश प्रत्येक मामले में अपराध के अनुरूप दी जाने वाली सजा का निर्धारण करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करता है? संहिता की धारा 235 की उपधारा (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद चुनाव करना होगा। वह उपधारा इस प्रकार है:

"यदि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायाधीश, जब तक कि वह धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता, सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा, और फिर कानून के अनुसार उसे सजा सुनाएगा।"

अभियुक्त की सुनवाई की आवश्यकता का उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के नियम को संतुष्ट करना है। यह निष्पक्षता की मूलभूत आवश्यकता है कि जो आरोपी अब तक अपराध के सवाल पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसे दोषी पाए जाने पर पूछा जाना चाहिए कि क्या उसके पास सजा के सवाल पर कहने के लिए कुछ है या देने के लिए कोई सबूत है। यह और भी अधिक आवश्यक है क्योंकि अदालतों को आम तौर पर सजा के मामले में व्यापक विवेक से चुनाव करना होता है। लगाई जाने वाली सही सजा का निर्धारण करने में न्यायालय की सहायता के लिए विधायिका ने धारा 235 में उप-धारा (2) पेश की। इसलिए उक्त प्रावधान दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है; यह प्राकृतिक न्याय के नियम को संतुष्ट करता है, जिसके अनुसार अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुनवाई का अवसर मिलता है और साथ ही अदालत को दी जाने वाली सजा का चयन करने में मदद मिलती है। चूंकि प्रावधान का उद्देश्य अभियुक्त को सजा के सवाल पर असर डालने वाली सभी प्रासंगिक सामग्री को अदालत के समक्ष रखने का अवसर देना है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रावधान हितकर है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य है और इसे महज औपचारिकता नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए, श्री गर्ग का यह शिकायत करना उचित था कि ट्रायल कोर्ट ने वास्तव में इसे महज एक औपचारिकता के रूप में लिया था, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने 31 मार्च, 1987 को दोषी पाए जाने से पहले उसी दिन अपराध का निष्कर्ष दर्ज किया था। और सजा के सदमे से उबरने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें सजा के सवाल पर कुछ कहना है और इसके तुरंत बाद दोनों आरोपियों को मौत की सजा देने का फैसला सुनाया गया। जैसा कि पहले कहा गया है, जीवन या मृत्यु के मामले में, पीठासीन अधिकारी को अभियुक्त की वैधानिक सख्ती के लिए उच्च स्तर की चिंता दिखानी चाहिए और इसे सजा का विकल्प चुनने से पहले पार की जाने वाली औपचारिकता मात्र नहीं मानना चाहिए। यदि विकल्प चुना जाता है, जैसा कि इस मामले में, अभियुक्त को अदालत के समक्ष अपने पूर्ववृत्त, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, कम करने और कम करने वाली परिस्थितियों आदि को रखने का एक प्रभावी और वास्तविक अवसर दिए बिना, सजा पर अदालत का निर्णय होगा असुरक्षित। हमें शायद ही यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि कई मामलों में सजा के निर्णय का अपराधी और उसके परिवार के सदस्यों पर विशुद्ध प्रशासनिक निर्णय की तुलना में कहीं अधिक गंभीर परिणाम होता है; एक फोर्टियोरी, इसलिए, फेयरप्ले का सिद्धांत बाद वाले की तुलना में पूर्व के मामले में अधिक ताकत के साथ लागू होना चाहिए। नागरिक परिणामों वाला एक प्रशासनिक निर्णय, यदि सुनवाई के बिना लिया जाता है तो आम तौर पर प्राकृतिक न्याय के नियम का उल्लंघन माना जाता है। इसी तरह संहिता की धारा 235 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं का अक्षरश: पालन किए बिना लिया गया सजा संबंधी निर्णय भी इसी तरह के भाग्य को पूरा करेगा और उसे उचित आदेश द्वारा प्रतिस्थापित करना पड़ सकता है। सज़ा सुनाने वाली अदालत को इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सज़ा के प्रश्न पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियाँ रिकॉर्ड पर लाई जाएँ। उसके सामने रखी गई कम करने वाली तथा विकट करने वाली परिस्थितियों को उचित महत्व देने के बाद ही उसे सजा सुनानी चाहिए। हमारा मानना है कि एक सामान्य नियम के रूप में ट्रायल कोर्ट को दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद मामले को भविष्य की तारीख के लिए स्थगित कर देना चाहिए और अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष को भी सजा के सवाल पर प्रासंगिक सामग्री रखने के लिए कहना चाहिए और उसके बाद सजा सुनानी चाहिए। अपराधी पर लगाया जाएगा. वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले बताया गया है, हमें डर है कि विद्वान ट्रायल जज ने संहिता की धारा 235 की उपधारा (2) की अनिवार्य आवश्यकता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। उच्च न्यायालय ने भी जब मृत्युदंड की पुष्टि की तो उसके पास विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखी गई अल्प सामग्री ही थी।

हमने पहले जो कहा है उसके अलावा, अब हम इस पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि क्या हत्या के दोषी पाए गए दो आरोपियों को मौत की सजा देना उचित है। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले के पैराग्राफ 42 से 44 में सजा के सवाल पर विचार किया है। ट्रायल कोर्ट के लिए जो कारण महत्वपूर्ण था वह यह है: यह अत्यधिक दोषीता के सबसे गंभीर मामलों में से एक है जिसमें दो निर्दोष और असहाय शिशुओं को बर्बर तरीके से मार डाला गया था। कम करने वाली परिस्थितियों पर ध्यान देने के बाद कि दोनों अपराधी विवाहित युवक थे जिनके बच्चे भी थे, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि चूंकि हत्याएं बिना उकसावे के और निर्दयी तरीके से की गई थीं, इसलिए नरमी की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि अपराध इतना घृणित था कि इसने चौंका दिया। न्यायालय का विवेक. उच्च न्यायालय ने उक्त दोनों अभियुक्तों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा के प्रश्न पर इस प्रकार विचार किया:

> "अलाउद्दीन मियां और केयामुद्दीन मियां की सजा को बरकरार रखा गया है, सवाल यह है कि क्या संदर्भ को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मौत की सजा को बरकरार रखा जाना चाहिए। मेरे विचार में अलाउद्दीन मियां और केयामुद्दीन मियां ने गंभीर घातक चोटें पहुंचाने में अत्यधिक मानसिक विकृति दिखाई है 7/8 साल और 7 महीने की उम्र की असहाय लड़कियां। इसलिए, मेरे विचार में, इस हत्या को दुर्लभतम मामलों में से एक माना जा सकता है। अलाउद्दीन मियां और केयामुद्दीन मियां द्वारा प्रदर्शित अत्यधिक मानसिक भ्रष्टता मुझे दी गई सजा को बरकरार रखने के लिए प्रेरित करती है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अलाउद्दीन मियां और केयामुद्दीन मियां पर।"

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि नीचे की अदालतें इस तथ्य से काफी प्रभावित हुईं कि पीड़ित निर्दोष और असहाय शिशु थे, जिन्होंने जिस निर्मम तरीके से उन्हें मार डाला था, उसके लिए उन्होंने कोई उकसावे की बात नहीं कही थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हत्याएं वीभत्स थीं. हालाँकि, प्रत्येक मामले की गंभीरता के अनुरूप सजाओं को उचित रूप से वर्गीकृत करने के लिए, यह आवश्यक है कि कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम सजा, जैसा कि बचन सिंह के मामले (सुप्रा) में देखा गया, 'दुर्लभतम' के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। दुर्लभ' मामले जो असाधारण प्रकृति के होते हैं। अपराध की गंभीरता को प्रतिबिंबित करने, कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने, अपराध के लिए उचित सजा प्रदान करने, आपराधिक आचरण के लिए पर्याप्त निवारक प्रदान करने और समुदाय को आगे इसी तरह के आचरण से बचाने के लिए गंभीरता की सजाएं दी जाती हैं। यह तीन प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करता है (i) दंडात्मक (ii) निवारक और (iii) सुरक्षात्मक। इसीलिए इस न्यायालय ने बचन सिंह के मामले में कहा कि जब सजा के विकल्प का प्रश्न विचाराधीन हो तो न्यायालय को न केवल अपराध और पीड़ित को बल्कि अपराधी की परिस्थितियों और अपराध के प्रभाव को भी देखना चाहिए। समुदाय पर. जब तक अपराध की प्रकृति और अपराधी की परिस्थितियाँ यह प्रकट न करें कि अपराधी समाज के लिए खतरा है और आजीवन कारावास की सजा पूरी तरह से अपर्याप्त होगी, न्यायालय को आम तौर पर पट्टादाता को सजा देनी चाहिए, न कि मौत की चरम सजा देनी चाहिए। केवल असाधारण मामलों के लिए आरक्षित रहें। मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1983] 3 एससीसी 470 के बाद के फैसले में, इस न्यायालय ने बचन सिंह के मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों को खारिज करने के बाद कहा कि केवल उन असाधारण मामलों में जिनमें अपराध इतना क्रूर, शैतानी और समुदाय की सामूहिक चेतना को झकझोर देने वाला विद्रोह, क्या मौत की सज़ा देना जायज़ होगा। वर्तमान मामले में, दुर्भाग्य से वाक्य के चयन के लिए सामग्री कम है। अपराध का कारण अस्पष्ट है, दोनों पक्षों के दो शिशुओं के बीच झगड़ा बताया गया है, जो सही प्रतीत नहीं होता है। हत्याएं लाभ के लिए नहीं थीं। आरोप से पता चलता है कि लक्ष्य पीडब्लू 6, पिता था, न कि दो शिशु। दोनों शिशुओं की

हत्या किसी भी आरोपी के ध्यान में नहीं थी. दोनों लड़कियाँ अपने लक्ष्य के भागने की हताशा के कारण अपराधियों के गुस्से का शिकार थीं। अपराध में ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं है जो मामले को असाधारण बना दे। केवल यह तथ्य कि शिशुओं को मार दिया जाता है, और अधिक के बिना, मामले को 'दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

बचन सिंह के मामले में उन मामलों को वर्गीकृत करने के लिए मानक निर्धारित करने के सवाल पर विचार किया गया, जिनमें मृत्युदंड लगाया जा सकता है और यह महसूस किया गया कि बिना प्रयास किए संहिता की धारा 354(3) के अनुरूप व्यापक दिशानिर्देशों को इंगित करना वांछनीय होगा। कठोर मानक तैयार करें। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि सजा प्रक्रिया के मानकीकरण से एक ही श्रेणी के मामलों में भी दोषीता में भिन्नता को ध्यान में रखने के लिए न्यायिक विवेक के लिए बहुत कम जगह बचेगी। वकील द्वारा बताई गई गंभीर परिस्थितियों (पैरा 202) और कम करने वाली परिस्थितियों (पैरा 206) का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि हालांकि 'ये प्रासंगिक कारक थे, लेकिन न्यायिक विवेक को बंधन में डालना वांछनीय नहीं होगा। इसमें बताया गया कि ये कारक संपूर्ण नहीं थे और चेतावनी दी गई थी: 'हमारे द्वारा बताए गए व्यापक उदाहरणात्मक दिशानिर्देशों की सहायता से अदालतें, संहिता की धारा 354(3) के अनुरूप, हमेशा अधिक ईमानदार देखभाल और मानवीय चिंता के साथ महत्वपूर्ण कार्य का निर्वहन करेंगी।' मच्छी सिंह के मामले में बाद के फैसले में, न्यायालय ने कठोरता लाने का प्रयास किए बिना उन मामलों के प्रकार को इंगित करने का प्रयास किया जो असाधारण वर्ग के अंतर्गत आ सकते हैं। फैसले को न्यायिक विवेक को बाधित करने के प्रयास के रूप में पढ़ना उचित नहीं होगा। यहां तक कि उस मामले में बताए गए प्रकार के मामलों में भी परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, जिसके लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, इस मामले की परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि अपराधियों ने दोनों लड़कियों की हत्या उनके प्रति किसी घृणा के कारण या अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपना लक्ष्य खो जाने की हताशा और क्रोध के कारण की थी। दुर्भाग्य से चूंकि ट्रायल जज ने दोषियों को सजा के सवाल पर विचार करने के लिए समय नहीं दिया, अपराध सामने आने का असली मकसद, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, मौका चूक गया। अभियुक्तों के पूर्ववृत्त, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ, समुदाय पर उनके अपराध का प्रभाव आदि रिकॉर्ड पर नहीं आए हैं। इन विवरणों की अनुपस्थिति सज़ा का चुनाव करना कठिन बना देती है। हमने पहले जो देखा है और जिन परिस्थितियों में हत्याएं हुईं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, हमें लगता है कि मौत की कठोर सजा की आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरूप दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। सभी शीर्षकों के तहत अभियुक्त संख्या 1 और 2 की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई है, लेकिन क्रमशः शाहना खातून और चांद तारा की हत्या के लिए उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। जहां तक आरोपी संख्या 3 से 6 का सवाल है, धारा 326/149, आईपीसी के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है; हालाँकि, अन्य शीर्षकों के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी गई है। यदि वे पहले ही अपनी सजा काट चुके हैं तो उनके जमानत बांड रद्द कर दिए जाएंगे; अन्यथा वे अपनी जमानत के लिए आत्मसमर्पण कर देंगे और शेष सजा काटेंगे। अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गईं।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।